

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, हनुमानगढ
पीठासीन अधिकारी :- हरभान मीणा, आर.ए.एस

अपील संख्या - 84/2013/225 आर टी ए

1. दीपचन्द जुहाराराम जाति जागिड़ ब्राह्मण निवासी ढिलकी जाटान तहसील नोहर।
 2. सरस्वती पत्नि सीताराम जाति जागिड़ ब्राह्मण निवासी ढिलकी जाटान तहसील नोहर।
- अपीलांटस

बनाम

1. रामसिंह पुत्र मुखराम जाति जागिड़ ब्राह्मण निवासी ढिलकी जाटान तहसील नोहर।
2. हेतराम पुत्र मुखराम जाति जागिड़ ब्राह्मण निवासी ढिलकी जाटान तहसील नोहर।
3. अमीलाल पुत्र मनीराम जाति जागिड़ ब्राह्मण निवासी ढिलकी जाटान तहसील नोहर।
4. भूराराम पुत्र मनीराम जाति जागिड़ ब्राह्मण निवासी ढिलकी जाटान तहसील नोहर।

---- रेस्पोंडेंटस

अपील विरुद्ध आदेश दिनांक 08.08.2013 न्यायालय सहायक कलैक्टर एवं उपखण्डाधिकारी
भादरा प्र0सं0 79/2013 अनवानी दीपचन्द आदि बनाम रामसिंह आदि

उपस्थित :-

श्री विजयसिंह कड़वासरा अधिवक्ता अपीलांटस

श्री हवासिंह पूनियां अधिवक्ता रेस्पोंडेंटस

निर्णय

दिनांक:-09.02.2018

1. प्रकरण के तथ्य संक्षेप मे इस प्रकार है कि अपीलांट ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक वाद अन्तर्गत धारा 88 व 188 आरटीए पेश कर इसके साथ एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आरटीए पेश किया जिसमे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय पारित करते हुए प्रार्थना पत्र अपीलांट खारिज कर दिया गया, जिससे व्यथित होकर अपीलाण्ट ने यह पेश की है।
2. उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की बहस सुनी गई।
3. विद्वान अधिवक्ता अपीलाण्ट ने अपनी बहस में कथन किया कि अपीलाधीन आदेश पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य के विपरीत होने के कारण खारिज योग्य है। अपीलांट की तरफ से प्रस्तुत बंटवारा रूपराम के तीनो बेटो के बीच अन्य खातेदारियों के साथ होने का तथ्य दर्ज है तथा उक्त बही की लिखित से उक्त भूमि रूपराम की होना साबित है तथा उक्त दस्तावेजात दावा मे साक्ष्य होने के पश्चात साबित होना था मगर विचारण न्यायालय ने अपने आदेश मे दावा का ही निर्णय कर दिया जबकि प्रार्थना पत्र 212 आरटीए मे तीन महत्वपूर्ण बिन्दूओ को साबित करना होता है जो अपीलांट ने भलीभांति साबित किया है। प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आरटीए पेश करने का मुख्य

उद्देश्य यह होता है कि मूल दावा तक वाद विषयवस्तु को संरक्षित रखना तथा जो काश्तकार जहां काबिज है तथा पुराने समय से पूर्वजो की खातेदारी भूमि लगातार काश्त करता आ रहा है तो नियमानुसार उसके हक व हिस्सा में कोई दखल अन्दाजी ना करें जिससे कोई वादग्रस्त भूमि के संबंध में कोई विवाद ना हो मगर विचारण न्यायालय ने इन बातों पर गौर ना कर कतई विधि विरुद्ध निर्णय पारित किया है जो काबिले खारिज है। अपीलांट के पक्ष में प्रथम दृष्टतया प्रकरण भलीभांति साबित था तथा प्रार्थना पत्र के तीनों महत्वपूर्ण बिन्दू साबित होते थे फिर भी विचारण न्यायालय ने अस्थायी निषेधाज्ञा मुताबिक इस्तदुआ जारी ना कर कानूनी गलती की है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अपीलाधीन निर्णय को निरस्त किया जावे तथा प्रार्थना पत्र सायलान/अपीलांट स्वीकार किया जाकर ताफैसला वाद मुताबिक इस्तदुआ गैरसायलान के खिलाफ अस्थायी निषेधाज्ञा जारी की जावे।

4. विद्वान अधिवक्ता रेस्पोंडेंट ने अपनी बहस में अपील में वर्णित तथ्यों का खण्डन करते हुए कथन किया कि वादग्रस्त भूमि कभी रूपराम की खातेदारी नहीं रही अपितु मुखराम की नौतोड़ की हुई भूमि थी जो मुखराम के जीवनकाल तक उनके कब्जा में रही व उनकी मृत्यु के बाद रेस्पोंडेन्ट्स के कब्जा काश्त में है तथा वे ही माल अदा करते हैं। अपीलांट का वाद भूमि में कोई हक व हिस्सा नहीं है ना ही उनका कभी कब्जा काश्त रहा है। अपीलांट ने ऐसा कोई रिकार्ड पेश नहीं किया है जिससे वाद भूमि पूर्वजो की मानी जावे। वादग्रस्त भूमि जो मुखराम के दर्ज है वह पूर्व में पूर्वजो के नाम दर्ज रही है, के संबंध में जमाबंदी रिकार्ड आदि प्रस्तुत नहीं किया गया है तथा कब उक्त भूमि पूर्वजो के नाम दर्ज थी तथा कब यह भूमि मुखराम के नाम दर्ज हो गई या मुखराम द्वारा करवाई गई, इसके संबंध में भी कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किये हैं। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण विधिवत प्रक्रिया अपनाते हुए विधिसम्मत अपीलाधीन निर्णय पारित किया है जो सही है। अतः अपील अपील खारिज योग्य होने के कारण अपील खारिज की जावे।

5. उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया व पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन करने के उपरांत निष्कर्ष है कि अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में संलग्न जमाबंदी रिकार्ड अनुसार वादग्रस्त भूमि वादग्रस्त भूमि मुखराम के नाम दर्ज थी और वर्तमान में भी मुखराम के नाम से दर्ज है। अपीलांत का तर्क है कि उक्त भूमि पूर्व में अपीलांत के दावा रूपराम के नाम दर्ज थी जो रूपराम की मृत्यु के बाद उसके तीनों पुत्रों मुखराम, जुहारराम, रामचन्द्र को बहिस्सा बराबर विरासतन प्राप्त हुई है परन्तु मुखराम ने छिपे तौर पर अकेले अपने नाम उक्त भूमि दर्ज करवा ली। जबकि अपीलांत द्वारा ऐसा कोई दस्तावेजी साक्ष्य ना तो अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया और ना ही दौराने अपील प्रस्तुत किया गया जिससे यह साबित हो सके कि वादग्रस्त भूमि पूर्व में मुखराम के नाम दर्ज ना होकर उनके पूर्वज रूपराम के नाम दर्ज रही हो तथा बाद में मुखराम द्वारा अकेले नाम अपने नाम दर्ज करवाई गई हो। प्रस्तुत रिकार्ड से भी यह साबित है कि वादग्रस्त भूमि मुखराम के नाम दर्ज है तथा वर्तमान जमाबंदी में भी वादग्रस्त भूमि मुखराम के नाम दर्ज है। सम्वत 2000 से भूमि लगातार आज तक मुखराम के नाम ही दर्ज चली आ रही होना साबित होता है। अपीलांत द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजी साक्ष्य के आधार पर प्रथम दृष्टयां मामला अपीलांत के पक्ष में साबित नहीं होता है। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय में बिना किसी औचित्य एवं प्रक्रियात्मक त्रुटि के हस्तक्षेप किया जाना न्यायोचित नहीं होने के कारण अपील अपीलांत सारहीन होने से खारिज किये जाने योग्य है।
6. अतः अपील अपीलांत सारहीन होने के कारण निरस्त की जाकर अधीनस्थ न्यायालय के अपीलाधीन निर्णय दिनांक 08.08.2013 को यथावत रखा जाता है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली निर्णय की प्रमाणित प्रति सहित लौटाई जावें। पत्रावली फ़ैसलशुमार होकर दाखिल दफ़तर हो।

निर्णय आज दिनांक 09.02.2018 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया

(हरभान मीणा आर.ए.एस.)
राजस्व अपील अधिकारी
हनुमानगढ़